pecuniary benefits are not the considerations of the bigness or smallness of the office. I agree with him. But this is also a fact that where there is an obvious difference between the pay of one individual and another and the other individual is a Constitutional authority, this is a glaric paradox, which has to be removed. In this connection I would again refer to—this is my point—clause (4) of article 148 of the Constitution, which says:

> "The Comptroller and Auditor-General shall not be eligible for further office either under the Government of India or under the Government of any State after he has ceased to hold his office."

You will appreciate, Madam, that while the Secretaries of the Government including the Cabinet Secretary, who is being equated in regard to pay with the Comptroler and Auditor-General, can and do take up appointments after their retirement in any public sector undertaking or Government advisory committee, the Comptroller and Auditor-General cannot and does not; under the Constitutional bar placed on him he cannot do this. Therefore, I beg of you coolly reconsider it and come out with an amendment at a very early date so that this anomaly is removed because I consider that with this Rs. 2,200, at least, the denigration, to my mind, will be rectified to some extent. This is my submission.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI MARGARET ALVA): Now, the question is:

> "That the Bill be passed."

The motion was adopted.

---

(1) STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE INDUSTRIES (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT ORDINANCE, 1984.

(II) THE INDUSTRIES (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 1984.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI MARGARET ALVA): We now take up the next item. The Industries (Development and Regulation) Amendment Bill, 1984.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: Let us take it tomorrow. It is already nearing 6 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI MARGARET ALVA): We have decided to sit till 6 P.M. Let us sit till 6 P.M. at least.

SHRI KALYAN ROY: I would request you. We have passed two Bills already. We have done our job for today.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI MARGARET ALVA): Mr. Jha is ready to move his Resolution

SHRI KALYAN ROY (West Bengal) We have done Calling Attention and these two Bills. Let the Minister move the Bill and let the discusion be taken up tomorrow. Let the discussion start, but let it not be concluded today. I was told that we have to sit up to 6 P. M. Now, it is being extended up to 6.30 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI MARGARET ALVA): We will sit only up to 6 O' clock.

SHRI KALYAN ROY: Some people may be prepared to sit till 6 A.M. But I am not prepared.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI MARGARET ALVA): Let us sit still 6 P. M. Mr. Jha is ready to move his Resolution. Let us finish this.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA (Bihar): Madam, I beg to move.

> "That this House disapproves the Indsutries (Development and Regulation) Amendment Ordinance, 1984 (No. 1 of 1984) promulgated by the President on the 12th January, 1984."

उपसभाध्यक्ष महोदया, हमारे सामने एक बहुत प्रतिष्ठित मंत्री है जिन की हम लोग इज्जत करते हैं और जो एक अच्छे वातावरण में रह चुके हैं : आचार्य नरेन्द्र देव जैसे हमारे नेता की संगति में वे रह चुके हैं।

[Shri Shiva Chandra Jha]

अब मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि इस आर्डिनेंस की क्या जरूरत थी जबकि हाउस बैठने जा रहा था 23 फरवरी से। यह जो 12 जनवरी को आपने आर्डिनेन्स जारी किया तो आप देखिए कि 12 जनवरी और 23 जनवरी तक कोई संविधान में प्रावधान नहीं है कि बगैर आर्डिनेन्स के हम काम कर सकें? जब आप जानते थे कि सैशन बैठ रहा है तो आर्डिनेन्स क्यों जारी किया? आप यह भी जानते है कि चैयर से भी कई बार यह कहा गया है, यह आदेश दिया गया है कि सरकार को जब सत्र बैठने जा रहा है तो आर्डिनेन्स की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपने उसकी अवहेलना की है। क्या वजह है आर्डिनेन्स लाने का? आर्डिनेन्स का तरीका मोटे तौर पर अनडेमोक्रेटिक है। हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा जो कांस्टीट्यूशनल ढांचा है, उसके मुताबिक काम हो। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस सरकार को नैक है आर्डिनेन्स लाने का। आप कहेंगे कैसे? मेरे पास आकड़े हैं। प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की सरकार अब तक 172 महीने रही है, 1966 से जोड़कर और इन्होंने कुल 179 आर्डिनेन्स जारी किये हैं। मोटे तौर पर एक आर्डिनेन्स एक महीने मे जारी होता है। तो क्या यह कहना गलत है कि यह सरकार आर्डिनेन्स की सरकार है। बगैर आर्डिनेन्स के यह सरकार टिक नहीं सकती है।

श्रीमन्, यह तो मामूली आर्डिनेन्स की बात है। अगर राज्यों की बात लें तो वह देख लें कि कितने आर्डिनेन्स जारी होते है। बिहार का एक उदाहरण है जिसे प्रेसिडेंट ने स्वीकृति दी है। पंजाब मे आपने मार्शल ला जारी कर दिया है, हरियाणा मे करने जा रहे हैं। आज के अखबारों में है तीन जिलों को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया है। सारे पंजाब और हरियाणा में करेंगे। क्या यह हमारे जनतांत्रिक ढांचे का खात्मा नहीं है? यह प्रवृति बहुत खराब है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हू कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने खुद इस प्रवृति के खिलाफ लेख लिखकर भारत की जनता को आगाह किया था, कलकत्ता के मार्डन रिव्यु में उन्होंने लिखा था हमको डिक्टेटर नहीं चाहिये। बार बार प्रेसिडेंट एक आदमी को बनाने से तानाशाही प्रवृति आती है। यह भावना नहीं होनी चाहिये कि जो डैमोक्रेटिक तरीका है उसके खिलाफ हम जायें। तो मैं आपसे इसकी सफाई चाहता हूं कि यह प्रवृति क्या हमारे जनतांत्रिक ढाचे के अनुकूल है। आपने इमरजैंसी में यह सब कुछ किया। यह करके आपने यह कालिमा हमारे जनतंत्र पर पोत दी जिसे मिटाया नहीं जा सकता। जिस तरह से चांद की कालिमा नहीं हट सकती है उसी तरह से इमरजैंसी की कालिमा नहीं हट सकती है। जिस तरह से प्रहार आपने किया जनतंत्र पर उसको खत्म करने का, वह कालिमा हट नही सकती। लेकिन देश की जनता ने उसका पुरजोर जवाब दिया। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि भारत की जनता जनतांत्रिक मूल्यों के लिए कामिटेड है। भारत की जनता इस बात की बर्दाशत नहीं करेगी कि यदि कोई इस ढांचे पर कुठाराघात करता है तो भारत की करोड़ों की जनता इसकी मुखालफत करेगी। 1977 में जो भारत की जनता ने मुकाबला किया वह आपको मालूम है। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक फिजां हमने देखी इमरजैंसी में, यही काम क्या आप फिर करोगे? यह थर्स्ट आपको प्रौपेल करेगा कि और हो और हो? डैमोक्रेटिक पावर हो, अथोरिटेरियन पावर आयेगी तो नतीजा यह होगा, सारा ढांचा

खत्म हो जायेगे। कहने के लिये आप संविधान में कानून पास करके करते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हिटलर कोई तलवार के जोर से नहीं आया। हिटलर आया वोट के जरिये री-स्टैग में। वोट के जरिये री-स्टैग में आकर वेमर रिपब्लिक में आग लगा दी और सब खत्म कर दिया। जनतंत्र ढांचे को खत्म करने का एक यह तरीका उसने अपनाया। आर्डिनेन्स भी वही प्रवृत्ति है। डेमोक्रेटिक ढांचा तो टु स्टेब इट फ्राम बेहाइन्ड टु माइन इट, उसको कमजोर करने का यह तरीका है। यह एक बहुत खतरनाक बात है। हम को सचेत रहना है। आप क्यों नहीं मुखालिफत करते कि आर्डिनेन्स नहीं होना चाहिये। सत्र आ रहा है हम सत्र में इस पर कानून बनायेंगे इसलिये आर्डिनेन्स नहीं आना चाहिये। लेकिन आप भी उसके मुताबिक चलने लग गये हैं।

जैसा आप विधेयक ला रहे हैं स्माल इंडस्ट्री की बाबत, स्माल इज ब्यूटीफुल। किसने कहा था? सुमेकर ने कहा था। और किसने कहा था गांधी जी ने कहा था। स्माल इज ब्यूटीफुल गांधी जी का दर्शन था। जो साध्य है, जो हमारा एम है वैसा ही साधन भी ऊंचा होना चाहिये। आपका साध्य जैसा है, आपका एम जैसा है वैसा ही आपका साधन का तरीका है। यह अनडेमोक्रेटिक है, यह अनगांधीयन का तरीका है। आप यह आर्डिनेन्स लाये-- चाहे जिस रूप में लाये स्माल इंडस्ट्री के नाम पर, उसको बढ़ावा देने के लिये। मैं जानता हूं इसमें पोटेन्शियलिटी है। मैं जानता हूं वह प्रोडक्शन जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री की है उसमें उसका हाथ है। इसमे डोमेस्टिक प्रोडक्शन का हाथ है, इसमे डायरेक्ट पोटेन्शियलिटी भी ज्यादा है। लार्ज स्केल में आप आधा मिलियन को एम्पलाई करते है। स्माल इंडस्ट्री जिसके लिये आप करना चाहते हैं उससे आपको 9 मिलियन ज्यादा पोटेन्शियलिटी मिलती है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है देहातों में। इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये दो बातों की देहात में बहुत जरूरत है--एक कम्युनिकेशन, रास्ता और दूसरा बिजली यानी पावर। चाहे बिहार हो, यू० पी० हो या कोई और इलाका हो, वे जो आपके उद्योग है वे नही बढ़ पायेंगे। सवाल यह है कि सारा तरीका जो आपका आर्डिनेन्स का है, इससे आप एक विशियस सर्किल में ला देते हैं। यह अनगांधीयन है, यह गांधी के दर्शन के खिलाफ है। हमारे जनतंत्र के आदर्श के खिलाफ है। हो सकता है वही हालत हो जो आज पंजाब के तीन जिलों मे इमरजेंसी लगा दी है और सारे पंजाब में हो जाए, हरियाणा में हो जाए, फिर डर है कही क्लेम्प सारे देश में न हो जाए। देश में ऐसा होगा तो देश निपट लेगा, यहां की जनता निपट लेगी। वह समय आने वाला है, अगला साल आने वाला है। जनता इसका फैसला कर लेगी। मैंने जो स्टेट्युटरी रेजोलूशन मूव किया है इसमें मुझे केवल इतना ही कहना है कि वह जो तरीका अनगांधीयन है, अनडेमोक्रेटिक है, जिसके मुतल्लिक चेयर ने भी कई बार आदेश दिया है ऐसा काम न करें जबकि सत्र होने वाला हो, फिर आपने क्यों किया? इसीलिये मैं इस आर्डिनेन्स की, इस अध्यादेश की पूरी ताकत से, मेडम चेयरमैन, आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरी मदद करेंगी, इसकी मुखालिफत करता हूं।

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): Madam, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

[Shri Narayan Datt Tiwari]

Madam, you are aware that it has been one of the most important policy measures adopted by the Government with the blessings of this House that the competitive strength of industrial undertakings in the small-scale sector should be reserved for selected items for exclusive production by small-scale undertakings. Under this policy, 872 items are presently so reserved. Government has been making such reservation ever since 19th February 1970 through the exercise of powers under section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 which provides that the Central Government, having regard to the smallness of the number of workers employed or the amount invested in the industrial undertakings or to the desirabliity of encouraging small undertakings from the operation of all or development of any scheduled industry may exempt any undertaking or class of undertakings generally, or, to the stage of any of the provisions of the Act.

Now, Madam as there has been no specific mention in section 29B of the Act, there have been doubts raised about the competence of the Government to take such action. The Bombay High Court, in a judgement last year in the case of Vindhya Paper Mills versus Union of India and another, had quashed Government's notification in so far as they provide for reservation of specific articles for exclusive manufacture in the small-scale sector. We had gone in appeal regarding this judgment but it was taking a long time. Without prejudice to the judgment, we were advised that we should bring this principle of reservation, especially those items which have already been reserved from time to time, beyond the pale of doubt. Otherwise, productivity was suffering, there was danger and there was uncertainty in the minds of small industries, and various associations representing small-scale industry were demanding that Government should come out with the necessary legislation so that Government has got the requisite power to reserve such items of industry.

I would like to assure my esteemed colleague, Shri Jha, that we are not enamoured of issuing Ordinances; there is no question; and I agree in principle with him that unless it is a matter of urgency, we should not legislate on the basis of Ordinances. I may also assure him that this question also was discussed in some detail. It was only to save some time because it was affecting the productivity of small industries and then there was a danger that some other undertakings which were not to undertake production of those particular reserved items might go into this activity surreptitiously. Therefore, we thought it fit that we should have an Ordinance to provide for this particular measure. Honourable Shri Jha has come out with some statistics. I would say that if our Founding Fathers of the Constitution had not thought of having such Ordinance-making power with Government, they would not have provided for it. Because we have this contingency built in our Constitution, it makes it amply clear that there might be situations in which we have to legislate on an emergent basis. Therefore, while I would like to refute the basic allegations which, of course, my esteemed colleague is sometimes prone to make, I would also humbly request him not to mix up this particular Ordinance with his general thesis which is difficult for me to controvert because I cannot orient him ideologically. But I thank him for having supported in substances, in principle, the issue behind this Ordinance. He has agreed in principle. I think it is

all the more necessary that the House should accept his Bill without any controversy and we should pass this Bill unanimously because it supports the small-scale sector. We are thinking of bringing a comprehensive legislation later on so that we can go into all matters pertaining to the small-scale sector. There are many facts to the many problems faced by the small-scale sector. So, in consultation with the Standing Committee on Small-Scale Industries, we propose to bring a comprehensive legislation later on. I am sure that this august House will bless this legislative measure by its sustained support and will give its approval to the policy of reservation for the small-scale industries.

The questions were proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI MARGARET ALVA): The Resolution and the Motion are now open for discussion. They will be taken up tomorrow.

The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at fifty-six minutes past five of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 6th March, 1984.

GMGIPNI—L—1893 RS—27-6-84—570